80वें स्वतंत्रता दिवस पर विशेष

विचार बिन्दु

राजस्थान : भारत की रेयर अर्थ तत्वों की राजधानी बनने की ओर

बीसवीं शताब्दी में जिस देश के पास तेल के बड़े भंडार थे, वही दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रभावित करता था। इक्कीसवीं शताब्दी में परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, पवन ऊर्जा, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान और आधुनिक रक्षा तकनीक का भविष्य रेयर अर्थ तत्वों (रेयर अर्थ इलेमेन्टस) और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भर होता जा रहा है। इसलिए आने वाले समय में जिस देश के पास इन खनिजों के साथ-साथ उनके प्रसंस्करण और उपयोग की तकनीक होगी, वही औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में आगे रहेगा। इसी बदलती वैश्विक स्थिति के बीच राजस्थान के लिए एक बड़ी संभावना सामने आई है। राजस्थान नई (एक्सप्लोरेशन लाईसेन्स) व्यवस्था के तहत रेयर अर्थ तत्वों के लिए का औपचारिक निष्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बना है। यह केवल प्रशासनिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि राजस्थान को भविष्य की उच्च-तकनीकी अर्थव्यवस्था से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण कदम है । रेयर अर्थ तत्व वास्तव में 17 धात्विक तत्वों का समूह है। इनमें लैंथेनम, सेरियम, प्रसीओडिमियम, नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम और टर्बियम जैसे तत्व प्रमुख हैं। इनका उपयोग ऐसे शक्तिशाली स्थायी चुंबक बनाने में होता है, जिनके बिना आधुनिक तकनीक के अनेक उपकरणों की कल्पना मुश्किल है। इलेक्ट्रिक वाहन, पवन टर्बाइन, ड्रोन, मिसाइल, रडार, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, हार्डडिस्क और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इन तत्वों का उपयोग होता है। यही कारण है कि इन्हें आज 'भविष्य की धातुएं' भी कहा जाता है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसके पास संसाधन होने के बावजूद रेयर अर्थ के उत्पादन और प्रसंस्करण की क्षमता अभी पर्याप्त विकसित नहीं हुई है। भारत के पास दुनिया के रेयर अर्थ खनिज भंडार का लगभग 6 प्रतिशत है, लेकिन वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी केवल लगभग 1 प्रतिशत है। अपनी जरूरत पूरी करने के लिए भारत को बड़ी मात्रा में इन खनिजों का आयात करना पड़ता है और लंबे समय से चीन पर उसकी निर्भरता काफी अधिक रही है। वर्ष 2018-19 में भारत ने अपने रेयर अर्थ आयात का लगभग 92 प्रतिशत मूल्य के आधार पर और 97 प्रतिशत मात्रा के आधार पर चीन से प्राप्त किया था। यह स्थिति बताती है कि भारत के पास संसाधन होने के बावजूद उनके खनन, प्रसंस्करण और उपयोग की क्षमता को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है । यह निर्भरता केवल आर्थिक मामला नहीं है। रेयर अर्थ तत्व आधुनिक रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और हरित ऊर्जा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इनकी आपूर्ति बाधित होने पर देश की रणनीतिक और औद्योगिक क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। चीन का वैश्विक रेयर अर्थ खनन और विशेष रूप से प्रसंस्करण पर मजबूत प्रभाव भारत सहित पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। इसी कारण भारत सहित अनेक देश अपने वैकल्पिक स्त्रोत विकसित करने और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने इस चुनौती को समझते हुए ( ) में संशोधन कर की नई व्यवस्था लागू की है और की खोज को प्राथमिकता दी है। इसी व्यवस्था के तहत राजस्थान ने रेयर अर्थ तत्वों के लिए का औपचारिक निष्पादन कर देश में अठाणी भूमिका निभाई है। यह लाइसेंस लगभग 207.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए जारी किया गया है। इसमें बालोतरा जिले की पचपदरा तहसील के कनावतला-देवीगढ़ तथा जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील का क्षेत्र शामिल है। प्रारंभिक भूवैज्ञानिक अध्ययनों में यहां लैंथेनम, सेरियम, प्रसीओडिमियम और नियोडिमियम जैसे महत्वपूर्ण रेयर अर्थ तत्वों की संभावनाएं सामने आई हैं। इस क्षेत्र का वैज्ञानिक अन्वेषण () द्वारा किया जाएगा। आधुनिक ड्रिलिंग, भू-भौतिकीय सर्वेक्षण, रासायनिक परीक्षण और त्रि-आयामी भू-मॉडलिंग के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि यहां उपलब्ध खनिज भंडार कितनी मात्रा में हैं और उनका आर्थिक उपयोग कितना संभव है।यदि राजस्थान में रेयर अर्थ तत्वों का वैज्ञानिक अन्वेषण सफल रहता है, तो पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक विकास का नया अध्याय शुरू हो सकता है। जिस प्रकार बाड़मेर के तेल भंडारों ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था और पहचान को बदला, उसी प्रकार रेयर अर्थ तत्व राज्य को उच्च-प्रौद्योगिकी उद्योगों का महत्वपूर्ण केंद्र बना सकते हैं। इससे केवल खनन के अवसर ही पैदा नहीं होंगे, बल्कि खनिज प्रसंस्करण, धातु निष्कर्षण, स्थायी चुंबक निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उच्च तकनीकी उद्योगों में भी निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। लेकिन असली सफलता केवल जमीन से खनिज निकालने में नहीं होगी। यदि राजस्थान केवल कच्चा अयस्क बाहर भेजता रहा, तो इस खनिज संपदा का बड़ा आर्थिक लाभ दूसरे राज्यों या देशों को मिल सकता है। इसलिए राजस्थान को अभी से पूरी औद्योगिक श्रृंखला विकसित करने की योजना बनानी चाहिए। यहां रेयर अर्थ पृथक्करण संयंत्र, धातु प्रसंस्करण इकाइयां, निर्माण केंद्र, अनुसंधान प्रयोगशालाएं और उच्च तकनीकी विनिर्माण उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए। इससे राजस्थान केवल खनिज उत्पादक नहीं, बल्कि रेयर अर्थ आधारित उद्योगों का केंद्र बन सकेगा। इस पूरी प्रक्रिया में राजस्थान के विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। भू-विज्ञान, धातुकर्म, पर्यावरण विज्ञान, मृदा विज्ञान और जल प्रबंधन के विशेषज्ञ मिलकर ऐसी तकनीक विकसित कर सकते हैं, जिससे औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालयों में रेयर अर्थ तत्वों से जुड़े अनुसंधान, प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक नई तकनीकी दक्षता प्राप्त होगी। रेयर अर्थ अयस्कों का प्रसंस्करण तकनीकी रूप से जटिल और महंगा है। इसके साथ पर्यावरण सुरक्षा, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी चुनौतियां भी जुड़ी हैं। पश्चिमी राजस्थान पहले से ही जल की कमी वाला क्षेत्र है। इसलिए यहां विकास का ऐसा मॉडल अपनाना होगा, जिसमें खनिज संसाधनों का उपयोग हो, लेकिन जल और पर्यावरण पर अनावश्यक दबाव न पड़े। स्थानीय लोगों की भागीदारी और उनके हितों की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। राजस्थान की रेयर अर्थ नीति तभी सफल मानी जाएगी, जब इसका लाभ स्थानीय क्षेत्र, राज्य और पूरे देश को मिले। राजस्थान के सामने आज एक दुर्लभ अवसर है। यह केवल एक नए खनिज की खोज का अवसर नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता में नेतृत्व करने का अवसर है। यदि अन्वेषण सफल होता है और राज्य दूरदर्शी औद्योगिक नीति अपनाकर खनिज प्रसंस्करण, विनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है, तो राजस्थान की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। बाड़मेर के तेल ने राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान दी थी। अब बालोतरा-जोधपुर क्षेत्र में रेयर अर्थ तत्वों की यह संभावना राजस्थान को भविष्य की तकनीकी अर्थव्यवस्था में नई पहचान दिला सकती है । जरूरत केवल खनिज निकालने की नहीं, बल्किखनिज से तकनीक और तकनीक से उद्योगबनाने की है। यदि राजस्थान यह कर सका, तो पश्चिमी राजस्थान की रेत से केवल दुर्लभ धातुएं ही नहीं निकलेंगी, बल्कि रोजगार, निवेश, हरित ऊर्जा, उच्च तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की नई संभावनाएं भी जन्म लेंगी।

प्रोफेसर (डा.) पी. सी. कंठालिया
पूर्व विभागाध्यक्ष (मृदा विज्ञान) एवं मुख्य वैज्ञानिक
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर

असली आज़ादी : जब देश गंदगी और बीमारियों से भी मुक्त होगा

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अस्वच्छता उन्मूलन का बिगुल बजा

के के गुप्ता

हर वर्ष 15 अगस्त 1947 को जब देश का तिरंगा पूरे गौरव के साथ आकाश में लहराता है और राष्ट्रगान की धुन करोड़ों भारतीयों के हृदय में राष्ट्रप्रेम का संचार करती है, तब हमारा मन स्वाभाविक रूप से 1947 की उस ऐतिहासिक सुबह की ओर लौट जाता है, जब भारत ने सदियों की पराधीनता की बेड़ियां तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह स्वतंत्रता हमारे असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम थी।

लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति तक सीमित नहीं है। आज, जब भारत अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब हमारे सामने आज़ादी का एक नया अर्थ और एक नई चुनौती भी मुँह बाए खड़ी है । वह है गंदगी से आज़ादी, बीमारियों से आज़ादी, प्रदूषण से आज़ादी, जल संकट से आज़ादी और नागरिक लापरवाही से आज़ादी। 1947 में हमने पराधीनता की बेड़ियां अवश्य तोड़ी थीं लेकिन अब समय है कि हम गंदगी, बीमारी और अस्वच्छ जीवनशैली की बेड़ियों को भी तोड़ें। यही विकसित भारत के संकल्प का अगला चरण है और यही स्वतंत्रता दिवस का सच्चा संदेश भी होना चाहिए।

हम अक्सर विकास का मूल्यांकन बड़ी सड़कों, ऊंची इमारतों, औद्योगिक निवेश और आधुनिक तकनीक से करते हैं। निस्संदेह ये विकास के महत्वपूर्ण मानक हैं, लेकिन किसी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति का सबसे बड़ा पैमाना उसके नागरिकों का स्वास्थ्य और उनके आसपास का स्वच्छ वातावरण है।यदि किसी गरीब परिवार की वर्षों की बचत बीमारी के इलाज में चली जाए, यदि दूषित पानी या गंदगी के कारण बच्चे बीमार पड़ें, यदि अस्वच्छ वातावरण के कारण कामकाजी लोगों की उत्पादकता प्रभावित हो, तो विकास की तस्वीर अधूरी रह जाती है।

बीमारी पर खर्च होने वाला पैसा केवल परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित नहीं करता, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी बोझ डालता है। इसके विपरीत, स्वच्छता पर किया गया प्रत्येक निवेश भविष्य के स्वास्थ्य खर्च को कम करने की दिशा में एक बड़ा महत्त्वपूर्ण निवेश है। बचा हुआ धन शिक्षा, कौशल, रोजगार, पोषण और बेहतर जीवन स्तर पर लगाया जा सकता है।इसलिए स्वच्छता केवल सफाई का विषय नहीं है बल्कि यह स्वच्छता ,स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण का विषय है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन देश में स्वच्छता को सरकारी कार्यक्रम की सीमा से बाहर निकालकर जन-आंदोलन बनाने की ऐतिहासिक पहल है। इस अभियान ने देश के करोड़ों नागरिकों को यह अहसास कराया है कि स्वच्छता केवल नगर निकायों या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इसी भावना को और व्यापक स्वरूप देने का प्रयास हो रहा है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि स्वच्छ शहर, स्वस्थ नागरिक और हरा-भरा राजस्थान ही विकसित राजस्थान की मजबूत नींव हैं।

स्वच्छता का लक्ष्य केवल कागजों पर उपलब्ध आंकड़ों में नहीं, बल्कि शहरों और गांवों की गलियों में दिखाई देना चाहिए। कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन हो, घर-घर से कचरा संठाहण प्रभावी हो, गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण हो, सार्वजनिक स्थान स्वच्छ रहें, नालियां साफ रहें, जल स्त्रोत सुरक्षित रहें और नागरिक स्वच्छता को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं-यही वास्तविक सफलता है।

दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर में नगर परिषद सभापति के रूप में काम करने का अवसर मेरे लिए केवल एक प्रशासनिक अनुभव नहीं, बल्कि स्वच्छता और नागरिक भागीदारी की शक्ति को समझने का महत्वपूर्ण अवसर भी रहा।डूंगरपुर जैसे शहर ने यह साबित किया कि बदलाव केवल बड़े महानगरों में ही संभव नहीं है। यदि राजनीतिक नेतृत्व की इच्छाशक्ति, प्रशासन की सक्रियता और नागरिकों की भागीदारी एक साथ जुड़ जाए तो छोटा शहर भी देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है।स्वच्छता और जल संरक्षण के क्षेत्र में डूंगरपुर के अनुभव ने मुझे यह विश्वास दिया कि भारत के प्रत्येक शहर में परिवर्तन की अपार संभावनाएं हैं। आवश्यकता केवल मात्र बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने वाली प्रशासनिक और नागरिक प्रतिबद्धता की है।यही कारण है कि स्वच्छ भारत मिशन से मेरा जुड़ाव मेरे लिए किसी पद या दायित्व से अधिक एक सामाजिक जिम्मेदारी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के प्रति मेरी सक्रिय भूमिका को देखते हुए मुझे राजस्थान में तीसरी बार स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का ब्रांड एम्बेसडर बनने का अवसर मिला है। यह सम्मान जितना गर्व का विषय है, उससे कहीं अधिक बड़ी जिम्मेदारी भी है।पिछले कई महीनों से मैं मुख्यमन्त्री भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान के सभी 41 जिलों का दौरा और समस्त स्थानीय निकायों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठकें कर स्वच्छता अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहा हूं। जहां कमियां दिखाई देती हैं, वहां उन्हें दूर करने के लिए सम्बंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को पाबन्द किया जा रहा है । यह यात्रा केवल अधिकारियों के साथ बैठकों तक सीमित नहीं है। मेरा प्रयास है कि जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, युवाओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को भी इस अभियान का सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

अब दूसरे चरण की बैठकों का क्रम भी शुरू हो चुका है। मेरा उद्देश्य स्पष्ट है-स्वच्छता के लक्ष्य फाइलों और रिपोर्टों में नहीं, बल्कि राजस्थान की हर गली और हर मोहल्ले में दिखाई दें।

हम सरकार से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह हमारे घर के बाहर सफाई करने के साथ-साथ हमारी आदतें भी बदल दे। नगर निकाय कचरा उठा सकता है, लेकिन नागरिक कचरा सड़क पर न फेंके-यह निर्णय नागरिक को स्वयं लेना होगा।सरकार नालियां बना सकती है, लेकिन उनमें प्लास्टिक और कचरा न डालने का संकल्प समाज को लेना होगा।

सरकार जल संरक्षण की योजनाएं बना सकती है, लेकिन पानी की एक-एक बूंद बचाने की आदत परिवारों को विकसित करनी होगी।यही कारण है कि स्वच्छता का सबसे बड़ा सैनानी कोई सरकारी कर्मचारी नहीं, बल्कि स्वयं जागरूक नागरिक ही है। यदि प्रत्येक भारतीय केवल इतना संकल्प ले ले कि न गंदगी करूंगा, न करने दूंगा, तो स्वच्छ भारत अभियान एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर भारत की जीवनशैली बन जाएगा। स्वच्छता और जल संरक्षण-दोनों एक ही लड़ाई के हिस्से

स्वच्छता को केवल कचरा उठाने तक सीमित करना भी सही नहीं होगा। स्वच्छता का संबंध हमारे जल स्त्रोतों, पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों को सँवारने से भी है।दूषित जल बीमारी का कारण बनता है। जल स्त्रोतों में कचरा डालना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक प्रदूषण आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट पैदा करता है। इसलिए स्वच्छता का अर्थ है-कचरे का उचित प्रबंधन, जल स्त्रोतों की रक्षा, पानी की बचत, वृक्षारोपण और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नागरिक व्यवहार।जब हम अपने शहर को साफ रखते हैं, तो हम केवल वर्तमान को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सुरक्षित करते हैं। स्वतंत्र भारत का सपना केवल इतना नहीं था कि देश अपना शासन स्वयं चलाए। सपना यह भी था कि प्रत्येक भारतीय सम्मान के साथ जीवन जी सके।सम्मानजनक जीवन का अर्थ है-स्वच्छ घर, स्वच्छ सड़क, स्वच्छ सार्वजनिक स्थान, सुरक्षित पेयजल, स्वस्थ पर्यावरण और बीमारी से बचाव की बेहतर व्यवस्था। इस दृष्टि से देखा जाए तो स्वच्छता सामाजिक न्याय और मानवाधिकार का भी विषय है। गंदगी का सबसे अधिक असर समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ता है। इसलिए स्वच्छ भारत वास्तव में एक अधिक समान और सम्मानजनक भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है।

15 अगस्त केवल उत्सव का दिन नहीं है। यह आत्ममंथन और संकल्प का भी दिन है।

इस वर्ष जब हम तिरंगे को सलाम करें, तो उसके साथ अपने शहर, अपने गांव और अपने मोहल्ले को भी स्वच्छ रखने का संकल्प भी लें। हम संकल्प लें-कि हम कचरा इधर-उधर नहीं फेंकेंगे।गीले और सूखे कचरे को अलग करेंगे।पानी की एक-एक बूंद का सम्मान करेंगे।सार्वजनिक स्थानों को अपना समझकर उनकी स्वच्छता बनाए रखेंगे।

प्लास्टिक के अनावश्यक उपयोग से बचेंगे। पेड़ लगाएंगे और पर्यावरण की रक्षा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण-गंदगी करने वाले को रोकने का साहस भी दिखाएंगे। डूंगरपुर में हमने घर और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के सामने कचरा डालने वालों पर जुर्माना लगाया था जिससे बहुत बड़ा परिवर्तन आया ।

हमने नगर की प्राचीन बावड़ियों की सफाई और जीर्णोद्धार कर नगर में पेयजल आपूर्ति के नए स्त्रोत विकसित किए थे । वर्षा जल के बचाव के लिए घरों में टंकिया बनवा और आसपास की ज़मीन में खड्डे खुदवा उसे छतों के पाइपों से जोड़ा था। उसके अभूतपूर्व परिणाम दिखें थे और वर्षों से सूखे हैण्ड पम्प भी चार्ज हो गए थे। पर्यावरण सुधार के लिए पोधारोपण, संग्रहित कचरा से बायोगैस प्लांट में बिजली उत्पादन,गोबर गैस प्लांट आदि अनेक प्रयोग और नवाचार किये गए थे । राष्ट्रभक्ति केवल सीमा पर खड़े सैनिक का कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रभक्ति उस नागरिक के व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए जो अपने शहर को साफ रखता है, पानी बचाता है, पेड़ लगाता है और सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर उसकी रक्षा करता है।

भारत ने 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की थी। आज हम आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से विश्व की अठाणी शक्तियों में शामिल होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य केवल आर्थिक आंकड़ों से पूरा नहीं होगा।इसके लिए स्वस्थ नागरिक चाहिए।स्वच्छ शहर चाहिए।सुरक्षित पर्यावरण चाहिए।जागरूक समाज चाहिए और ऐसी नागरिक संस्कृति चाहिए जिसमें स्वच्छता किसी अभियान की मोहताज न हो।

राजस्थान इस दिशा में देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में स्वच्छ, स्वस्थ और हरियालों राजस्थान का जो संकल्प आगे बढ़ रहा है, उसकी सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब सरकार के प्रयासों के साथ समाज की इच्छाशक्ति भी जुड़े।मैं राजस्थान के सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और विशेषकर युवाओं से इस स्वतंत्रता दिवस पर आ ान करता हूं कि वे स्वच्छता को केवल एक सरकारी कार्यक्रम न मानें, बल्कि इसे अपने जीवन का संस्कार बनाएं।

आइए, इस 15 अगस्त को तिरंगे के सामने एक ऐसा संकल्प लें जो आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भारत दें।1947 में हमने पराधीनता की बेड़ियां तोड़ी थीं।अब हमें गंदगी, बीमारी और लापरवाही की बेड़ियां तोड़नी हैं।

यही अमृतकाल का सच्चा संकल्प है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव है। और यही स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के प्रति हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।क्योंकि असली आज़ादी तभी होगी, जब भारत स्वच्छ होगा।

भारत स्वस्थ होगा और हर नागरिक जागरूक होगा।हम स्वाधीनता दिवस पर यह संकल्प लें कि हम न गंदगी करेंगे, न करने देंगे। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत ही सशक्त भारत है।

- के.के. गुप्ता-
ब्रांड एम्बेसडर, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), राजस्थान

1947 का सबसे बड़ा प्रश्न : भारत के संवैधानिक विकल्प कब समाप्त हुए?

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 1946-47 के दस्तावेजों, निर्णयों और मानवीय अनुभवों की पुनर्पड़ताल

डॉ. मुकेश शर्मा

17 अगस्त 1947। भारत स्वतंत्र हो चुका था। पाकिस्तान भी अस्तित्व में आ चुका था, लेकिन पंजाब और बंगाल की अंतिम सीमाएं इसी दिन सार्वजनिक हुईं। स्वतंत्रता के दो दिन बाद रैडक्लिफ़ सीमा आयोग का निर्णय सामने आया, यानी अनेक लोगों ने स्वतंत्रता का सूर्योदय इस अनिश्चितता के बीच देखा कि उनका गांव, शहर या घर आखिर किस देश का हिस्सा होगा। यह केवल प्रशासनिक तथ्य नहीं था, यह उस असाधारण गति और अनिश्चितता का भी संकेत था, जिसके बीच विभाजन और सत्ता हस्तांतरण को कार्यान्वित किया जा रहा था। यहीं से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का सबसे कठिन प्रश्न जन्म लेता है। क्या भारत का विभाजन वास्तव में एकमात्र विकल्प था या उससे पहले ऐसे संवैधानिक अवसर मौजूद थे जो धीरे-धीरे राजनीतिक समर्थन और विश्वास खोते गए?

इस प्रश्न का पहला महत्वपूर्ण उत्तर 16 मई 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में मिलता है। स्वतंत्रता से लगभग पंद्रह महीने पहले प्रस्तुत इस योजना ने तत्काल विभाजन को अंतिम समाधान नहीं माना। उसने एक ढीले संघीय ढांचे में संयुक्त भारत की परिकल्पना की, जिसमें रक्षा, विदेश नीति और संचार केंद्र के विषय होते और शेष अधिकांश अधिकार प्रांतों के पास रहते। यह व्यवस्था सफल होती या नहीं, यह अलग प्रश्न है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि मई 1946 तक संयुक्त भारत केवल भावनात्मक आकांक्षा नहीं, बल्कि एक औपचारिक संवैधानिक विकल्प था।

यहीं इतिहास किसी एक व्यक्ति या दल को दोषी ठहराने के बजाय निर्णयों की पूरी शृंखला की जांच मांगता है। कांठोस और मुस्लिम लीग, दोनों किसी चरण पर कैबिनेट मिशन की रूपरेखा से जुड़ीं, लेकिन उसकी व्याख्या समान नहीं थी। प्रांतीय समूहों की व्यवस्था, केंद्र की शक्तियों, प्रतिनिधित्व और अंतरिम सरकार को लेकर अविश्वास बढ़ता गया। 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों की अपनी स्वीकृति वापस लेते हुए पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए ' ' का निर्णय लिया। इसके बाद कलकत्ता, नोआखली, बिहार और फिर पंजाब की हिंसा ने राजनीतिक मतभेदों को सामाजिक भय और असुरक्षा में बदल दिया। प्रश्न अब केवल संविधान का नहीं था, नागरिकों की सुरक्षा और प्रशासन की क्षमता का भी था।

विभाजन के इतिहास की यही वह मानवीय परत है, जो राजनीतिक और संवैधानिक आख्यानों में अक्सर पीछे छूट जाती है। सरकारी अभिलेख बताते हैं कि निर्णय कैसे और किन परिस्थितियों में लिए गए? प्रत्यक्षदर्शियों की स्मृतियां बताती हैं कि उन निर्णयों की वास्तविक कीमत किसने और कैसे चुकाई? निस्संदेह स्मृति दस्तावेज का विकल्प नहीं है और मौखिक साक्ष्यों की आलोचनात्मक जांच आवश्यक है, लेकिन उन्हें इतिहास से बाहर रखना भी उसके मानवीय पक्ष को अधूरा छोड़ देना होगा। गलियों, गांवों, घरों और विस्थापन के रास्तों पर जो घटा, वह विभाजन का वह इतिहास है, जिसे सरकारी फाइलें पूरी तरह दर्ज नहीं कर सकतीं।

इस कहानी में एक और तथ्य विशेष ध्यान मांगता है। 16 मई 1947 तक कांठोस के दस्तावेजों में कैबिनेट मिशन की रूपरेखा संदर्भ-बिंदु बनी हुई थी। कांठोस की ओर से तैयार एक नोट में कहा गया कि वह इस योजना को अब भी आधार मानती है और मुस्लिम लीग के साथ समझौते के लिए उसमें परिवर्तन स्वीकार करने को भी तैयार है। इसका अर्थ यह नहीं कि उस समय संयुक्त भारत आसानी से बचाया जा सकता था, बल्कि यह बताता है कि संवैधानिक विकल्पों का अंत किसी एक दिन अचानक नहीं हुआ। वे राजनीतिक परिस्थितियों के दबाव में क्रमशः संकुचित होते गए।

और फिर आता है समय का प्रश्न।

20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि सत्ता हस्तांतरण जून 1948 से आगे नहीं जाएगा, किंतु 3 जून 1947 तक तस्वीर बदल चुकी थी। नई योजना सामने आई और कुछ ही सप्ताह बाद 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हो गए। इस बीच प्रशासन, सेना, वित्त, संपत्ति, सेवाओं, अभिलेखों और सीमाओं के विभाजन जैसी असाधारण जिम्मेदारियां भी पूरी करनी थीं।

इसलिए एक कठिन प्रश्न स्वाभाविक है, यदि फरवरी में जून 1948 तक का समय निर्धारित था तो सत्ता हस्तांतरण अगस्त 1947 तक क्यों सिमट गया? 3 जून के आधिकारिक ब्रिटिश वक्तव्य और माउंटबेटन के प्रसारण से स्पष्ट है कि सत्ता शीघ्र हस्तांतरित करने की इच्छा राजनीतिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए प्रश्न केवल ब्रिटिश जल्दबाजी का नहीं है, यह भी देखना होगा कि भारतीय नेतृत्व के लिए शीघ्र सत्ता हस्तांतरण क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया था? क्या इस समय-संकुचन ने वैकल्पिक समझौते, सीमांकन, नागरिक सुरक्षा और पुनर्वास की तैयारी के लिए उपलब्ध अवसर कम कर दिए? यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि समय-संकुचन ही हिंसा का कारण था, किंतु इसकी भूमिका की गंभीर जांच से बचा भी नहीं जा सकता।

कांठोस नेतृत्व के निर्णयों की पड़ताल भी इसी कसौटी पर होनी चाहिए। 1947 के मध्य तक क्या शीघ्र सत्ता हस्तांतरण, प्रभावी केंद्रीय शासन और बढ़ती हिंसा को रोकने की आवश्यकता संयुक्त भारत की संवैधानिक संभावनाओं पर भारी पड़ चुकी थी? दूसरी ओर, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग और ' ' की राजनीति तथा ब्रिटिश सरकार की सत्ता-हस्तांतरण नीति, इन तीनों को एक साथ देखे बिना विभाजन की जिम्मेदारी को समझना संभव नहीं है।

इसलिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का सबसे बड़ा प्रश्न केवल यह नहीं होना चाहिए कि 1947 में कौन दोषी था? उससे कहीं बड़ा प्रश्न यह है कि 2047 का भारत ऐसा क्या करे कि मतभेद मनभेद में, मनभेद अविश्वास में और अविश्वास उस स्थिति में न बदले, जहां संवाद और संवैधानिक समाधान की गुंजाइश ही समाप्त होने लगे। इतिहास का सर्वोच्च सम्मान केवल उसकी त्रासदियों को स्मारकों में सुरक्षित रखना नहीं है। उसकी सबसे कठिन सीख को राष्ट्रीय चरित्र, सार्वजनिक नीति और लोकतांत्रिक आचरण का स्थायी हिस्सा बना देना है।

स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती

हम जमीनी स्तर की किशोरी युवाओं का एक समूह हैं जो विभिन्न संचार माध्यमों (आलेख और कविताएं) से अपने गांवों के जेंडर और अन्य सामाजिक मुद्दों को उजागर करना चाहते हैं। ऐसे सामाजिक मुद्दे जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

महासचिव, अखिल भारतीय संत समिति
डॉ. मुकेश शर्मा, लेखक एवं स्तम्भकार

राशिफल शनिवार 15 अगस्त, 2026

पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, शुक्ल पक्ष, तृतिया तिथि,शनिवार, विक्रम संवत 2083, आश्लेषा नक्षत्र प्रातः 6:07 तक, वारियान योग दिन 12:16 तक, किस्तुघ्न करण प्रातः 9:54 तक, चन्द्रमा प्रातः 6:07 से सिंह राशि में संचार करेगा।

मेष
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आज आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। आज आपसी ईर्ष्या-वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

धनु
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। परिवार में आपसी मतभेद हो सकते हैं।

वृष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

कन्या
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज मन में असंतोष बना रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

मकर
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

मिथुन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक परेशानी दूर होने लगेगी।

तुला
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित योजना का क्रियान्वयन होगा। आज आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आज विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। आज मानसिक तनाव दूर होने लगेगा। मन:स्थिति में सुधार होगा।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से सम्पन्न हो सकते हैं। आज आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय दूर होगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आज व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।